

साफ संदेश बनाम विरोधी स्वर

आज जमीन पर लोगों की भावना क्या है? भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आए चार चुनाव परिणाम हैं, जो सच की झलक दिखा रहे हैं।

हम दिलचस्प समय में रहते हैं। भारत में राजनीतिक विरोध, जिसने पिछले छह वर्षों में बार-बार चुनावी विफलताओं का सामना किया है, उसे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन के मददेनजर एक मौका महसूस हो रहा है। विरोध कर रहे नेता संसद में चर्चा के बाद पारित किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों में विरोध ने एक बदसूरत व्यक्तिगत मोड़ ले लिया है। कुछ लोग सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं।

इन विरोधों के बीच भारत का राजनीतिक पैमाना क्या कह रहा है? जमीन पर लोगों की भावना क्या है? भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आए चार चुनाव परिणाम सामने

हैं, जो सच की झलक दिखा रहे हैं।

आइए, सबसे पहले हम भारत के उच्च प्रौद्योगिकी वाले शहर हैदराबाद का मुआयना करते हैं। नवंबर के मध्य में विपक्ष को घेरने के लिए तेलंगाना सरकार ने जीएचएमसी चुनावों की तारीख 1 दिसंबर घोषित कर दी थी। यह स्पष्ट था कि विपक्ष (यानी भारतीय जनता पार्टी) को घेरने की पूरी तैयारी थी, ताकि उसे जनता से संवाद करने का ज्यादा मौका न मिले और चुनाव जीत लिया जाए। ऐसे में, चुनाव अभियान संक्षिप्त, पर उच्चस्तरीय था। और जब चुनाव परिणाम आए, तो उसने राजनीतिक टिप्पणीकारों को चौंका दिया और तेलंगाना राजनीति की दिशा बदलने का इरादा भी जाहिर कर दिया। वर्ष 2015-2016 के जीएचएमसी चुनावों में मात्र चार सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 48 सीटों तक पहुंच गई। पिछली बार के विपरीत पार्टी ने अपने बूते चुनाव लड़ा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस निगम में 99 सीटों से गिरकर 56 पर आ गई। हैदराबाद में भाजपा के मत प्रतिशत में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, मध्य वर्ग के बीच खासकर अच्छा प्रदर्शन किया और उन क्षेत्रों में भी, जहां बाढ़ राहत को

प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय सूचना एवं
प्रसारण मंत्री



लेकर राज्य सरकार की उदासीनता सामने आई थी।

हैदराबाद की यह जीत इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा कभी भी ताकत नहीं थी। यहां साल 2018 के अंत तक कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी थी। हैदराबाद स्थानीय चुनाव और डब्लक विधानसभा सीट पर हुए उप-चुनाव में मिली जीत ने भाजपा को 2023 विधानसभा में चुनाव जीतने की दौड़ में मजबूती से ला खड़ा किया है। चूंकि जीएचएमसी के चुनाव को कागजी मतपत्र के उपयोग से आयोजित किया गया, अतः भाजपा के विरोधियों को ईवीएम का बहाना भी नहीं मिला।

यदि हैदराबाद में भाजपा का शहरी स्तर पर विस्तार एक कहानी कहता है, तो राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य को भी देख लेना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार मजबूती से कायम है और विधानसभा चुनाव अभी तीन साल दूर हैं। यहां जब जिला पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव हुए, तब जमीन पर यही विचार था कि कांग्रेस अपने विरोधियों को बुहारकर बाहर कर देगी।

यहां भी चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक निकले। अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के 13 जिलों में काबिज है और अब कांग्रेस के पास केवल पांच जिले हैं। प्रदेश कांग्रेस समिति के मुखिया हों या राज्य सरकार के शीर्ष मंत्री और यहां तक कि सचिन पायलट के क्षेत्र, कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। इसके बाद हुए शहरी चुनावों में भी भाजपा का संघर्ष उत्साहजनक रहा।

राजस्थान में वोट करने वाले मतदाता मोटे तौर पर

किसान, ग्रामीण जन और मजदूर थे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसान विरोध या आंदोलन के स्थान भी हैं। फिर भी, जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, सभी के देखने योग्य हैं। उधर, असम के लोग भी अपनी कहानी साझा करने का इंतजार कर रहे थे। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के लिए हाल ही में मतदान हुआ और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी यूपीपीएल ने क्रमशः 9 और 12 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। इस चुनाव में कांग्रेस और एयूडीएफ के बीच जमीनी समन्वय देखा गया, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। इन बीटीसी चुनाव में काफी संख्या में आदिवासी मतदाता भी शामिल थे। उनका विश्वास व्यक्तिगत रूप से भाजपा, एनडीए व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अटूट है।

हैदराबाद हो, राजस्थान या असम, भाजपा नए क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है, मतदाताओं के साथ उसका जुड़ाव गहरा हो रहा है। गोवा में भी, जहां साल 2012 से भाजपा सत्ता में है, वहां उसने जिला पंचायत चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस यहां मजबूत प्रदर्शन के करीब तक न पहुंच सकी। गोवा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण ईसाई आबादी वाला राज्य है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर आदिवासी क्षेत्रों तक, और शहरी भाग से महानगरीय तटीय परिदृश्य तक, भारत एक संदेश दे रहा है। विविध मतदाता, विविध चुनाव एक ही संदेश दे रहे हैं कि साल 2020 में भारत का प्रमुख मुद्दा विकास है और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए ही इसे आकार प्रदान कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना महामारी को नियंत्रित किया है, आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है, जिस तरह से उन्होंने गरीबों की तब मदद की है, जब वे सबसे ज्यादा संकट में थे, उससे उन्होंने मतदाताओं के साथ एक तालमेल बिठा लिया है। राजनीतिक विपक्ष, जो इन चुनावों में से प्रत्येक में प्रधानमंत्री या कृषि कानूनों के विरोध में जनादेश देखना चाहता था, उसे बार-बार मुंह की खानी पड़ी है। भारत स्पष्ट रूप से आज एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहा है, जहां सुशासन और स्थिरता की राजनीति विरोध के बनावटी और निहित स्वार्थी एजेंडों पर भारी पड़ रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

